राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 18618/2023

भारतीय जीवन बीमा निगम, अधिकृत अधिकारी के माध्यम से, भारतीय जीवन बीमा निगम, ओ-2, अंबाजी औद्योगिक क्षेत्र, रीको गेस्ट हाउस के पास, आबूरोड, जिला सिरोही (राजस्थान)----- याचिकाकर्ता।

बनाम

समुंदर सिंह पुत्र श्री मानसिंह, ग्राम- जामथा, निवासी तहसील और जिला-सिरोही (राजस्थान)---उत्तरदाता।

याचिकाकर्ता (ओं) के लिएः- श्री राजीव पुरोहित।

प्रत्यर्थी (ओं) के लिएः- श्री त्रिभुवन सिंह।

माननीय न्यायाधीश डॉ. नूपुर भाटी

आदेश

10/01/2024

रिपोर्ट योग्य

1. वर्तमान रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दायर की गई हैः - (i) किसी उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश द्वारा, विद्वत स्थायी लोक अदालत, सिरोही द्वारा पारित दिनांक 03.10.2023 (अनुलग्नक-8) के आक्षेपित अधिनिर्णय को कृपया रद्द किया जाए और दरकिनार किया जाए। (ii) कोई अन्य उचित आदेश या निर्देश, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित समझता है, कृपया याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया जाए।

(iii) रिट याचिका की लागत कृपया याचिकाकर्ता को दिया दी जाए।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता-निगम से अपनी पत्नी श्रीमती लीला कंवर के नाम पर दो एल. आई. सी. पॉलिसियां ली थीं, जिसमें से एक पॉलिसी जिसका नंबर 155856827 है, एल. आई. सी. आधारशिला योजना 944 के तहत 3 लाख रुपये का बीमा कवर था, जिसका वार्षिक प्रीमियम 10,604/- रुपये था और दूसरी पॉलिसी धारक नंबर 155856828 में एल. आई. सी. न्यू एंडोमेंट प्लान 914 के तहत रुपये 10 लाख का बीमा कवर था जिसका छमाही प्रीमियम रुपये 19,518/- था। उपरोक्त पॉलिसियाँ 28.10.2021 को जारी की गई थीं। पॉलिसियाँ उपरोक्त तिथि पर जारी की गई थीं, लेकिन जीवन बीमा निगम को धोखा देने के इरादे से पॉलिसी धारक ने 28.05.2021 (जो नियमों में अनुमेय है) से पॉलिसी शुरू करने की तारीख चुनी, हालांकि, सिजेरियन ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी के तथ्य को छुपाया। यदि कॉलम में सिजेरियन डिलीवरी के तथ्यों का उल्लेख किया गया होता, तो याचिकाकर्ता ने सर्जरी के छह महीने से पहले पॉलिसी धारक के पक्ष में पॉलिसी जारी नहीं की होती। 23.12.2021 को, प्रतिवादी की पत्नी की मंदार स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। प्रत्यर्थी की पत्नी की मृत्यु के बाद, याचिकाकर्ता-निगम ने बीमा दावे का भुगतान नहीं किया और उससे व्यथित होने के कारण, प्रत्यर्थी ने कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22 के तहत विद्वान स्थायी लोक अदालत, सिरोही के समक्ष एक आवेदन को प्राथमिकता दी। याचिकाकर्ता ने एक लिखित बयान दायर किया और विद्वान स्थायी लोक अदालत ने 03.10.2023 के आदेश के माध्यम से आवेदन की अनुमति दी और याचिकाकर्ता-निगम ने उसी से व्यथित होने के कारण, वर्तमान रिट याचिका को प्राथमिकता दी।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी सभी भौतिक तथ्यों का खुलासा करने के लिए कर्तव्यबद्ध था जिसमें प्रतिवादी की पत्नी द्वारा किया गया उपचार यानी 23.06.2021 (अनुलग्नक-4) पर सिजेरियन ऑपरेशन भी शामिल है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रस्ताव प्रपत्र में, "स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत और पारिवारिक विवरण" के शीर्ष के तहत, प्रतिवादी की पत्नी ने भौतिक तथ्य को छुपाया और 'नहीं' में जवाब दिया, जबकि, 'बीमारी' के कॉलम में उपचार की आवश्यकता होती है और कोई भी ऑपरेशन किया जाता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी के दावे को अस्वीकार करने का एकमात्र कारण भौतिक तथ्यों का दमन था और विद्वान स्थायी लोक अदालत ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता-निगम को धोखा दिया है क्योंकि एल. आई. सी. पॉलिसी ली गई थी और 28.10.2021 को जारी की गई थी और पॉलिसी के शुरू होने की तारीख को 28.05.2021 से चुना गया था, इस तथ्य को छिपाते हुए कि प्रतिवादी ने 23.06.2021 को सिजेरियन सेक्शन किया था और यदि सिजेरियन डिलीवरी के तथ्य का उल्लेख आवश्यक कॉलम में किया गया होता, तो याचिकाकर्ता-निगम ने सर्जरी के छह महीने से पहले पॉलिसी जारी नहीं की होती जो दिशानिर्देशों से भी परिलक्षित होती। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि 11.05.2018 (अनुलग्नक-3) को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, कुछ शर्तें/बीमाकरण चिकित्सा स्थिति/बीमारियां/जटिलताएं हैं, जहां जीवन बीमा पॉलिसी उस अवधि के लिए जारी नहीं की जा सकती है क्योंकि ऑपरेशन छह महीने से अधिक का है जिसमें लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन (LSCS) भी शामिल है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रत्यर्थी की पत्नी (अनुलग्नक-9) द्वारा भरे गए प्रस्ताव प्रपत्र

की ओर भी अदालत का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि कॉलम 'सी' में याचिकाकर्ता जो "सामान्य जांच, अवलोकन, उपचार या ऑपरेशन के लिए किसी अस्पताल या नर्सिंग होम में प्रवेश के संबंध में जानकारी से संबंधित है?, यदि हां, तो विवरण दें", प्रतिवादी ने 'नहीं' कहा था और यह भी प्रस्तुत किया था कि कॉलम No.14 के खिलाफ "कोई भी ऑपरेशन, दुर्घटना या चोट/कोई शारीरिक दोष या विकृति", प्रतिवादी ने 'नहीं' का उल्लेख किया था, जबकि, प्रतिवादी ने 23.06.2021 को सिजेरियन ऑपरेशन किया था और उक्त प्रस्ताव प्रपत्र प्रतिवादी द्वारा भरा गया था। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी की पत्नी द्वारा 23.06.2021 को किए गए सिजेरियन सेक्शन के कारण, उसने एक बच्चे को जन्म दिया और 23.12.2021 को दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई, जो अनुलग्नक-5,सरकारी अस्पताल द्वारा जारी बाहरी पर्ची से स्पष्ट है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील शाखा प्रबंधक, बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य बनाम दलबीर कौर रिपोर्ट 2020 ए. आई. आर. एस. सी. 5210 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले पर भरोसा करते हैं और प्रस्तुत किया कि फैसले में निर्धारित कानून के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है जो निम्नानुसार हैः -

“एक प्रस्तावक जो जीवन बीमा की पॉलिसी प्राप्त करना चाहता है, वह इस मुद्दे से संबंधित सभी भौतिक तथ्यों का खुलासा करने के लिए कर्तव्यबद्ध है कि क्या बीमाकर्ता प्रस्तावित जोखिम को ग्रहण करना उचित समझेगा।"

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान मामला जीवन बीमा पॉलिसी से संबंधित है जो एक मेडिक्लेम पॉलिसी से पूरी तरह से अलग है। (2009) 8 एस. सी. सी. 316 में रिपोर्ट किए गए सतवंत कौर संधू बनाम न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड

के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा हैः-"एक मेडिक्लेम पॉलिसी एक गैर-जीवन बीमा पॉलिसी है जिसका उद्देश्य पॉलिसी धारक को चोट, दुर्घटनाओं या अस्पताल में भर्ती होने से संबंधित कुछ खर्चों के संबंध में आश्वस्त करना है। फिर भी, यह अनुबंध उबेर्रीमे फिदेई की श्रेणी में आने वाला बीमा का अनुबंध है, जिसका अर्थ है बीमाकृत की ओर से अत्यंत सद्भावना का अनुबंध। इस प्रकार, इस बात पर बहुत कम जोर देने की आवश्यकता है कि जब प्रस्ताव प्रपत्र में किसी विशिष्ट पहलू पर जानकारी मांगी जाती है, तो एक बीमाकृत उस विषय पर जानकारी का सही और पूर्ण प्रकटीकरण करने के लिए एक गंभीर दायित्व के तहत होता है जो उसकी जानकारी में है। यह निर्धारित करना प्रस्तावक का काम नहीं है कि मांगी गई जानकारी पॉलिसी के उद्देश्य के लिए है या नहीं। बेशक, खुलासा करने का दायित्व केवल उन तथ्यों तक फैला हुआ है जो आवेदक को ज्ञात हैं और न कि उन्हें क्या पता होना चाहिए था। प्रकट करने का दायित्व अनिवार्य रूप से किसी के पास मौजूद ज्ञान पर निर्भर करता है। उस ज्ञान की भौतिकता के बारे में उनकी राय क्षणभंगुर नहीं है।"

5. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी की पत्नी को गर्भावस्था के कारण 23.06.2021 को विधिवत भर्ती किया गया था और उसने सिजेरियन सेक्शन के माध्यम से 23.06.2021 को बच्चे को जन्म दिया और उसे 25.06.2021 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई जो डिस्चार्ज सारांश (अनुलग्नक-4) से स्पष्ट है। प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि संबंधित अस्पताल से छुट्टी मिलने पर, याचिकाकर्ता के पक्ष में एक प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-4) जारी किया गया था जो यह प्रमाणित करता है कि याचिकाकर्ता को सामान्य और स्वस्थ स्थिति में 25.06.2021 को अस्पताल से छुट्टी दी गई थी जो दर्शाता है कि प्रत्यर्थी की पत्नी के

26.03.2021 को सिजेरियन सेक्शन से गुजरने के बाद कोई जटिलता नहीं थी।

6. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी की पत्नी ने कॉलम No.14 के खिलाफ प्रस्ताव प्रपत्र भरते समय कोई भौतिक तथ्य नहीं छिपाया है, आवश्यक जानकारी किसी भी ऑपरेशन, दुर्घटना या किसी चोट/किसी शारीरिक दोष/विकृति के संबंध में थी, लेकिन वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी की पत्नी को कोई बीमारी या कोई दुर्घटना या चोट या कोई शारीरिक दोष या विकृति नहीं हुई थी और इसलिए प्रत्यर्थी की पत्नी द्वारा किए गए सिजेरियन सेक्शन को प्रस्तावित योजना की धारा III के कॉलम No.14 के तहत प्रकट करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रत्यर्थी के विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि जहाँ तक प्रस्तावित योजना की धारा III के कॉलम 'सी' के खिलाफ दी जाने वाली जानकारी की आवश्यकता थी, किसी भी अस्पताल या किसी नर्सिंग होम या उपचार या ऑपरेशन में प्रवेश के संबंध में जानकारी दी जानी आवश्यक थी और चूंकि प्रत्यर्थी की पत्नी को कभी भी किसी भी बीमारी के संबंध में किसी भी उपचार या ऑपरेशन के उद्देश्य से भर्ती नहीं किया गया था, इसलिए उसने तदनुसार उक्त कॉलम में 'नहीं' चिह्नित किया था।

7. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि सरकारी अस्पताल द्वारा 23.12.2021 को जारी डिस्चार्ज सारांश के अवलोकन पर, यह दर्शाता है कि प्रत्यर्थी की पत्नी की मृत्यु का कारण सीने में तेज दर्द और सांस फूलना था, जिसके कारण उसकी पत्नी को ऑक्सीजन सांद्रक पर रखा गया था और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए, प्रत्यर्थी की पत्नी की मृत्यु 23.06.2021 को उसके द्वारा किए गए सिजेरियन सेक्शन से संबंधित नहीं है।

8. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सुनवाई की गई तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

9. मान लीजिए, प्रत्यर्थी की पत्नी का 23.06.2021 को सिजेरियन सेक्शन हुआ और बच्चे का जन्म 23.06.2021 को हुआ और प्रत्यर्थी की पत्नी को 25.06.2021 को छुट्टी दे दी गई और वह सामान्य स्वस्थ स्थिति में थी जैसा कि अनुलग्नक-4 से पता चलता है जो रिकॉर्ड में रखा गया है। प्रत्यर्थी की पत्नी ने 28.10.2021 को 28.05.2021 से दो जीवन बीमा पॉलिसियाँ ली थीं। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यर्थी की पत्नी किसी भी पूर्व बीमारी से पीड़ित नहीं थी क्योंकि दोनों पक्षों द्वारा कोई चिकित्सा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी और सिजेरियन सेक्शन से गुजरने के बाद उसे स्वस्थ स्थिति में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी और इसलिए किसी चिकित्सा बीमारी के कारण ही प्रत्यर्थी की पत्नी को 23.12.2021 को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और एक घंटे के बाद भर्ती होने की उसी तारीख को वह गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। पॉलिसीधारक की चिकित्सा स्थिति/चिकित्सा विवरण मांगने का उद्देश्य यह है कि यदि पॉलिसी लेने वाला कोई व्यक्ति किसी भी बीमारी से पीड़ित है, तो निगम पॉलिसी जारी करने से पहले ऐसी बीमारी, यदि कोई हो, का खामियाजा वहन करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और वर्तमान मामले में, यदि प्रतिवादी की पत्नी के पास कोई पूर्व-चिकित्सा स्थिति मौजूद थी और उसे प्रस्ताव प्रपत्र भरते समय छुपाया गया था और ऐसी पूर्व-चिकित्सा स्थिति के कारण, प्रतिवादी की पत्नी की मृत्यु हो गई थी, तो ऐसी स्थिति में, पॉलिसी धारक के बीमा दावे को अस्वीकार करने का याचिकाकर्ता का निर्णय उचित होता, हालांकि, वर्तमान मामले में, कोई पूर्व-चिकित्सा स्थिति मौजूद नहीं थी और प्रतिवादी की कोई पूर्व-चिकित्सा स्थिति नहीं थी।

10. प्रत्यर्थी की दिवंगत पत्नी 35 वर्ष की आयु की एक बहुत ही युवा महिला थी और किसी भी तरह की दृष्टि से कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि वह बच नहीं पायेगी और असामयिक मृत्यु

होगी और इसलिए, प्रत्यर्थी या उसकी पत्नी ने याचिका दायर करने वाले को धोखा देने के इरादे से नीति नहीं ली होगी। चूँकि सी-सेक्शन की तारीख से मृत्यु की तारीख तक लगभग छह महीने का अंतराल था, इसलिए सी-सेक्शन को प्रतिवादी की पत्नी की मृत्यु का कारण नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि मृत्यु का कारण सी-सेक्शन होता, तो सी-सेक्शन की जानकारी प्रस्तुत न करना दावेदार के लिए घातक होता। याचिकाकर्ता-निगम एक राज्य संगठन होने के नाते, जिसने दावेदार को एक कल्याणकारी नीति दी है, उसे एक संपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था और एक बार जब दावेदार की ओर से धोखाधड़ी का कोई इरादा नहीं है, तो लाभ दावेदार को दिया जाना चाहिए। केवल, अधिकतम सी-सेक्शन की जानकारी नहीं देना दावेदार द्वारा दी गई एक अधूरी जानकारी कहा जा सकता है जो याचिकाकर्ता के लिए कोई अवैधता का कारण नहीं बनेगी और याचिकाकर्ता इसे दावेदार द्वारा किए गए दावे पर कोई असर किए बिना एक अधूरी जानकारी के रूप में मान सकता है। बीमित व्यक्ति को यह आभास था कि युवती जीवित रहेगी या उसका जीवन लंबा होगा क्योंकि वह किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं थी और परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, उसके द्वारा पॉलिसी ली गई थी। यदि बीमित व्यक्ति ने सी-सेक्शन के आगे घुटने टेक दिए होते, तो यह कहा जा सकता था कि उसने सी-सेक्शन से गुजरने के तथ्य को छिपा दिया था और याचिकाकर्ता-निगम को दावे को अस्वीकार करने में उचित ठहराया जाता, जबकि वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है। इस प्रकार, वैध अपेक्षा जो कानून में स्थापित एक सिद्धांत है, इस मामले में लागु होना चाहिए और दावा दावेदार को दिया जाना चाहिए और इस प्रकार, स्थायी लोक अदालत, सिरोही द्वारा पारित 03.10.2023 के आदेश को बरकरार रखा जाता है।

11. याचिका के गुण-दोष रहित होने के कारण इसे खारिज

किया जाता है। स्थगन आवेदन के साथ-साथ अन्य सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, भी खारिज किए जाते हैं।

(डॉ. नूपुर भाटी), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।